# फ़ैज अहमद फ़ैज की ग़ज़लें

(1)

दोनों जहान तेरी मुहब्बत में हार के,
वो जा रहा है कोई शबे-ग़म गुज़ार के

वीरों है मयकद:, खुमो-सागर उदास है
तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के

इक फुर्सते-गुनाह मिली, वो भी चार दिन
देखे हैं हमने हौंसले परवरदिगार के

दुनिया ने तेरी याद से बेगान: कर दिया
तुझसे भी दिलफरेब है ग़म रोज़गार के

भूले से मुस्करा तो दिए थे वो आज 'फ़ैज़'
मत पूछ वलवले दिले-नाकर्द:कार के

(2)

राज़े-उल्फत छुपा के देख लिया
दिल बहुत कुछ जला के देख लिया

और क्या देखने को बाकी है
आप से दिल लगा के देख लिया

वो मिरे हो के भी मेरे न हुए
उनको अपना बना के देख लिया

आज उनकी नज़र में कुछ हमने
सबकी नज़रें बचा के देख लिया

'फ़ैज़' तकमीले-ग़म भी हो न सकी
इश्क़ को आज़मा के देख लिया

(3)

नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं
क़रीब उनके आने के दिन आ रहे हैं

जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है
सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं

अभी से दिलो-जां सरे-राह रख दो
के लुटने-लुटाने के दिन आ रहे हैं

टपकने लगी उन निगाहों से मस्ती
निगाहें चुराने के दिन आ रहे हैं

सबा फिर हमें पूछती फिर रही है
चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं

चलो 'फ़ैज़' फिर से कहीं दिल लगाएं
सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं

(4)

तुम आए हो न शबे-इन्तिज़ार गुज़री है
तलाश में है सहर बार-बार गुज़री है

जुनूं में जितनी भी गुज़री ब-कार गुज़री है
अगरचे दिल पे ख़राबी हज़ार गुज़री है

हुई है हज़रते-नासेह से गुफ़्तगू जिस शब
वो शब ज़रूर सरे-कू-ए-यार गुज़री है

वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था
वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है

न गुल खिले हैं, न उनसे मिले, न मय पी है
अजीब रंग में अब के बहार गुज़री है

चमन पे ग़ारते-गुलची से जाने क्या गुज़री
क़फस से आज सबा बेक़रार गुजरी है

(5)

तुम्हारी याद के जब ज़ख़्म लगते हैं
किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं

हसीदे-यार के उनवां निखरने लगते हैं
तो हर हरीम में गेसू संवरने लगते हैं

हर अजनबी हमें मरहम दिखायी देता है
जो अब भी तेरी गली से गुज़रने लगते हैं

सबा से करते हैं ग़ुर्बत-नसीब ज़िक्रे-वतन
तो चश्मे-सुब्ह में आंसू उभरने लगते हैं

वो जब भी करते हैं इस नुत्को-लब की बखिय:गरी
फ़ज़ा में और भी नग्मे बिखरने लगते हैं

दरे-क़फस पे अंधेरे की मुहर लगती है
तो 'फ़ैज़' दिल में सितारे उतरने लगते हैं

## पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। आपने सच लिखा है कि ग़रीबों के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए अलग। जिस समाज में राठौर रूपी भेड़िये उच्चतम पदों पर बैठ कर कुछ भी अनैतिक कार्य करना चाहें तो उन्हें बचाने की कोशिश होती है। यही राठौर के साथ भी है। ऐसे राठौरों को सजा मिलेगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। आग्रह है कि कुछ हल्की-फुलकी चीजें भी छापें। वैसे आठ पेज के इस अख़बार से इतनी ज़्यादा जानकारी मिलती है जो अन्य किसी से शायद ही मिल पाये। इस अंक में प्रकाशित लेख और व्यंग्य आदि अच्छे लगे। हर अंक में आप एक बेहतरीन कविता का प्रकाशन कर रहे हैं। कृपया इस सिलसिले को बनाये रखें।

**-राजरानी, गुड़गांव**

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। सभी खबरें और लेख आदि पसंद आया। आप व्यंग्य प्रत्येक अंक में प्रकाशित करें। आपने पहले हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लेख छापा था। आप इस सिलसिले को जारी रखें। पहले जब परसाई जी मैगजीनों के लिए कॉलम लिखते थे तो उसका पहले से ही प्रचार होता था कि अमुक अंक से परसाई जी का व्यंग्य छपने जा रहा है। ग्राहक एडवांस में अपनी प्रति के लिए बुकिंग करा लें। और सचमुच, लोग अख़बार-मैगज़ीन के वितरकों को एडवांस पैसा थमा कर चले आते थे। ऐसी थी परसाई की लोकप्रियता। गपशप का कॉलम आपने अच्छा निकाला है। गंभीर रचनाओं को पढ़ने के बाद इससे अच्छा मनोरंजन हो जाता है।

**-सीमा कुमारी, दिल्ली**

अख़बार का अंक मिला। सारी सामग्री लाजवाब है। कोपेनहेगेन शिखर सम्मेलन के बारे में लेखक ने खरी बात कही है। दूसरे लेख और व्यंग्य आदि भी अच्छे लगे।

**- राकेश, गुड़गांव**

मैं इस अख़बार के माध्यम से नगर निगम का ध्यान गंदगी की समस्या की तरफ खींचना चाहता हूं। शहर में जहां देखिये कचरे के भरमार नज़र आते हैं। इन्हीं कचरों में पैदा होते हैं मच्छर जो शाम ढलते ही लोगों को काट खाने लगते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि मच्छरों के काटने से कितने तरह की बीमारियां होती हैं। क्या नगर निगम ने कचरा निस्तारण की कोई नीति बनाई है या सब कुछ यूं ही छोड़ दिया है। अब तो चुनाव वाली गहमागहमी शुरू होने वाली है। जो भी कहें, गंदगी इस शहर की पहचान है। इसलिए गंदगी हटा दी जायेगी तो शहर की पहचान ही लुप्त हो जायेगी। संभवत: पहचान कायम रखने के लिए गंदगी जमा कर के रखी जाती है।

**- रामचंद्र शर्मा, फरीदाबाद**

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। पहले की भांति ही सारी सामग्री बेबाक है। रेडक्रॉस के नाम पर जो खुली गुंडागर्दी हो रही है, उस पर क्या ज़िलाधीश का कोई नियंत्रण नहीं है? बात यह है कि अब तो हर ऐरा-गैरा मुख्यमंत्री से अपने संबंध होने की बात कर लोगों को, चाहे वे पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो, डराने लगता है। इससे मुख्यमंत्री की बड़ी बदनामी हो रही है। अगर अभी भी उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है तो इस संबंध में लोगों से साफ़-साफ़ कहें कि उनके नाम पर कोई अवैध कमाई करना चाहता है तो उसे सीधा अंदर किया जाये। अंक में प्रकाशित अन्य लेख भी काफ़ी पसंद आये।

**-शंभूनाथ, फरीदाबाद**

## पेज 1 का शेष भाग

**ईएसआई हस्पतालों पर केंद्र ने राज्यों को फटकारा, ठीक से काम करो या काम छोड़ो**

इससे राज्य सरकार ने अपने हिस्से का योगदान दो करोड़ तो बचा लिया परंतु राज्य की जनता को तो 16 करोड़ का नुक्सान हो गया। दूसरी ओर, इसी वित्तीय वर्ष में ईएसआई के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ़ के वेतन पर हरियाणा सरकार को मिला 46 करोड़ जबकि खर्च हो गया 63 करोड़। इससे राज्य सरकार को 17 करोड़ का सीधा घाटा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों ने वेतन-खर्च बढ़ा दिया। राज्य सरकार ने दिमाग़ का इस्तेमाल किये बिना इस घाटे को पूरा करने के लिए एक करोड़ तो दवाओं से बचा लिया तथा काफ़ी कुछ स्टाफ़ एवं सेवा को घटा कर पूरा करना चाहा। जबकि कारपोरेशन ने इस समस्या को पहले ही ताड़ लिया था और 1.1.09 को सभी राज्य सरकारों को जारी अपने एक पत्र द्वारा इसका समाधान सुझाते हुए वेतन खाते पर लगी सीमा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। लेकिन इसके लिए कारपोरेशन ने निम्न लिखित कुछ शर्तें रखीं जिससे ईएसआई की सेवायें बेहतर ढंग से चल सकें तथा धनाभाव से प्रभावित न हों।

पहली शर्त तो यह लगाई कि ईएसआई मानकों के अनुसार डॉक्टरों व स्टॉफ की नियुक्ति की जाये। इसके अनुसार अकेले फरीदाबाद में भी डिस्पेंसरियों व हस्पतालों के लिए 210 डॉक्टर नियुक्त करने पड़ेंगे जबकि फ़िलहाल 110 से काम को घसीटा जा रहा है। यहां 110 तो स्वीकृत पद हैं जबकि वास्तविक तैनाती तो 80 से भी कम है। इसी अनुपात में शेष स्टॉफ़ भी रखना होगा। दूसरी शर्त यह रखी कि वित्तीय शक्तियां चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों की अपेक्षा कार्यक्षेत्र में तैनात अधिकारियों के पास होनी चाहिएं जिससे कि वे अपनी जरूरत की वस्तुओं के लिए बार-बार चंडीगढ़ के चक्कर काटने की अपेक्षा स्वयं खरीद कर सकें। तीसरे, हस्पतालों के लिए बनी विकास कमेटियां पूर्णतया सक्रिय होकर काम करें। विदित है कि फरीदाबाद ईएसआई हस्पताल में भी ऐसी एक कमेटी एक वर्ष से बनी पड़ी है। इसका अध्यक्ष हस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक तथा उप चिकित्सा अधीक्षक कन्वीनर होता है। इसके अतिरिक्त दो श्रमिक तथा दो मालिकान के प्रतिनिधि और एक ईएसआई लोकल ऑफ़िस का मैनेजर होता है। इस प्रकार यह दस सदस्यीय कमेटी हस्पताल का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए गठित तो कर दी गई, परंतु इसे उच्चाधिकारियों द्वारा कभी चलने नहीं दिया गया, क्योंकि इस कमेटी द्वारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दो लाख रुपये प्रति आइटम खर्च करने की शक्ति मिलती है जबकि डाइरेक्टर के पास केवल एक लाख की है और एमएस के ऊपर बैठे सिविल सर्जन को मात्र 50,000 की है। तो ऐसे में भला ऊपर बैठे अफ़सर कैसे चलने दें कमेटियों को? चौथी शर्त, सभी दवायें रेट कांट्रेक्ट से खरीदी जायें। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है और शर्त भलीभांति लागू है।

लेकिन पांचवी शर्त सरकारी लालफीताशाही के गले नहीं उतर पा रही। इसके अनुसार तमाम पैसा सरकारी खज़ाने के माध्यम से खर्चने के बजाये वेतन के अलावा सारा पैसा एक रिवाल्विंग फ़ंड के माध्यम से खर्च किया जाये। मौजूदा व्यवस्था में ईएसआई कारपोरेशन अपने हिस्से का पूरा पैसा राज्य सरकार के खजाने में जमा करा देती है, जिसे निकाल कर खर्च करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खजाने वाली व्यवस्था में समय पर पैसा तो मिलता नहीं और 31 मार्च को वह लैप्स हो जाता है। जबकि उक्त रिवाल्विंग फ़ंड, जिसे कारपोरेशन व राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलायेंगी, में न तो खजाने की अड़चन और न ही 31 मार्च की पाबंदी। इस फ़ंड से एमएस को दो की बजाय 15 लाख, सिविल सर्जन को 50 लाख तथा डायरेक्टर को एक करोड़ तक वार्षिक खर्च करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। ईएसआई के लिए सभी प्रकार की खरीददारी फ़िलहाल डीएस एंड डी विभाग द्वारा की जाती है। इस विभाग को पूरे राज्य के लिए करीब 12 से 14 हज़ार करोड़ की खरीददारी करनी पड़ती है। इसलिए ईएसआई की छुटमुट खरीददारी की ओर न तो उसका कोई ध्यान होता है और न ही फुर्सत। इसलिए कारपोरेशन चाहती है कि ईएसआई की सारी खरीददारी डीएस एंड डी के बजाय राज्य सरकार व कारपोरेशन की एक संयुक्त कमेटी करे।

अंतिम शर्त यह है कि ज्यों ही ईएसआईसी राज्य के किसी क्षेत्र को नोटिफ़ाई करके अपनी योजना लागू करती है, राज्य सरकार तुरंत वहां पर डिस्पेंसरियां एवं हस्पताल आदि खोले। आज भी हरियाणा में ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां ईएसआई के नाम पर श्रमिकों के वेतन की कटौती तो होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। इसी के चलते कारपोरेशन को अपने विस्तार पर रोक लगानी पड़ती है। जबकि इस प्रकार के नये क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने का पूरा खर्चा तीन साल तक कारपोरेशन स्वयं वहन करती है। राज्य सरकार को एक धेला भी नहीं खर्चना होता। यदि सरकार इस शर्त पर गत दस वर्षों में अमल करती तो ईएसआई की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अधिक विस्तार हो चुका होता।

राज्य सरकार के बाबुओं को जो बात समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि वर्ष 2009-10 में वेतनों पर 50 करोड़, दवाओं पर 18.75 करोड़ तथा विशेष चिकित्सा पर तीन करोड़ जो कुल मिला कर हुआ 72 करोड़ रुपया। इसमें से 9 करोड़ सरकार ने तथा 63 करोड़ कारपोरेशन ने वहन किया। अब 2010-11 में, क्योंकि बीमाकृतों की संख्या बढ़ कर 7.5 लाख हो गई है, इसलिए अनुमानित बजट कुछ इस प्रकार होगा-वेतनों पर 70 करोड़, दवाओं पर 21 करोड़। विशेष चिकित्सा के खर्चे को पूर्ण रूप से कारपोरेशन द्वारा वहन करने का निर्णय ले लिया गया है। तो भी कुल बजट हो गया 91 करोड़ का। अब चूंकि हरियाणा सरकार के बाबू ईएसआई नियमों की बजाये काम को अपने तरीके से धकेलना चाहते हैं तो ईएसआई इस 91 करोड़ का सातवां भाग देने की बजाये कुल 71 करोड़ ही देगी, यानी राज्य सरकार को 11.36 की बजाये पूरे 20 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसके विपरीत यदि राज्य सरकार ईएसआईसी की शर्तों को मान लेती है तो बजट तो 91 से बढ़ कर 144 करोड़ का हो जायेगा और राज्य सरकार का हिस्सा 20 से घट कर मात्र 18 करोड़ रह जायेगा। दूसरे शब्दों में, राज्य की जनता को 144 करोड़ की सुविधायें प्राप्त होंगी जबकि राज्य सरकार का खर्च 20 करोड़ से घट कर 18 करोड़ रह जायेगा। पर यह बात इन नालायकों की समझ में कब आयेगी? जानकारों के मुताबिक मज़दूर मोर्चा के 1-15 दिसबंर अंक में इस बाबत विस्तृत जानकारी प्रकाहशित होने के बाद जहां एक ओर केंद्रीय श्रम मंत्री ने जहां राज्य सरकारों को फटकारा है, वहीं राज्य सरकार के बाबू भी कुछ हरकत में आये हैं। समझा जाता है कि ईएसआईसी द्वारा जारी 11.1.09 का पत्र भी इन बाबुओं ने फ़ाइलों की ढेर में से खोज निकाला है और उसे पढ़ने के बाद समझने व गुणा-भाग करने में जुटे हैं। जाहिर है, इस तरह के काम में कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है जिसे करने की आदत ये लोग़ बिल्कुल छोड़ चुके हैं। शायद केंद्र सरकार की फटकार और श्रमिकों के दबाव से ये लोग़ कुछ हाथ-पैर हिला लें।

अंत में यही कहा जा सकता है कि उनकी और उनकी पार्टी की नीतियों का चरमोत्कर्ष होता उनका प्रधानमंत्री बन जाना - कुछ महीनों के लिए ही सही। संभावना यह भी थी कि ऐसा होता तो वे नेहरू के आगे भी जा सकते थे और भारत के तेंग सियाओ पेंग भी बन सकते थे।